भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-210
10/12/2024 को उत्तरार्थ

विषयः रबी फसलों की लागत
***210. श्री नवीन जिंदलः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में शीत ऋतु में बोई जाने वाली विभिन्न (रबी) फसलों की लागत कितनी है;
(ख) शीत ऋतु की ऐसी कौन-कौन सी फसलें हैं जिनकी खरीद की व्यवस्था की गई है; और
(ग) विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय ऐसे व्यापक उपाय अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनमें स्वामित्व वाली पूंजी का अनुमानित मूल्य तथा भूमि संबंधी किराया शामिल है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'रबी फसलों की लागत' के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 210* के भाग (क) से (ग) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण

(क): रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2025-26 हेतु, सरकार द्वारा निर्धारित 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एवं उत्पादन लागत संबंधी विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गये हैं:

(₹ प्रति क्विंटल में)

क्र. सं.	फसल	उत्पादन लागत	एमएसपी
1	गेहूं	1182	2425
2	जौ	1239	1980
3	चना	3527	5650
4	मसूर (लेंटिल)	3537	6700
5	रेपसीड/सरसों	3011	5950
6	कुसुम्भ	3960	5940

(ख): सरकार द्वारा सभी छ: अधिदेशित रबी फसलों की खरीद की व्यवस्था की गई है। गेंहूँ एवं जौ के संदर्भ में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करती हैं। जब कभी भी दलहनों यथा चना एवं मसूर (लेंटिल) और तिलहनों यथा रेपसीड/सरसों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है तब इन उपजों की खरीद, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत की जाती है।

(ग): एमएसपी के निर्धारण में उत्पादन लागत (सीओपी) एक महत्वपूर्ण कारक है। अपनी मूल्य नीति की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) सभी लागतों पर व्यापक रूप से विचार करता है जिसमें भुगतान की गई सभी लागतें और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है।

केन्द्रीय बजट 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

*****